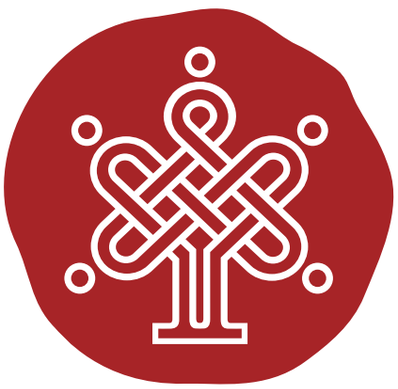

नालंदा
युनिवर्सिटी

वार्षिक रिपोर्ट
नालंदा विश्वविद्यालय

2013-2014

प्राक्कथन

वर्ष 2013–2014 में, विश्वविद्यालय आने वाले साल के पहले सत्र के छात्रों के दाखिले की तैयारी में व्यस्त रहा।

शासकीय मोर्चे पर, विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कम्बोडिया, लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, म्यंमार, न्यूजीलैण्ड, सिंगापुर, कोरिया गणराज्य और चीनी जनवादी गणराज्य के साथ अंतर सरकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन विश्वविद्यालय को हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ नेटवर्क और सहयोग बढ़ाने में मदद देगा। इस दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण कदम हेडक्वार्टर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना था, जिसके तहत विश्वविद्यालय विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को विश्वविद्यालय के लिए नियुक्त कर सकता था। बाहरी मामलों की संसद की स्थायी समिति द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल, 2013 में सुझाए गए संशोधनों को केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने अनुमोदन प्रदान कर दिया।

राजगीर में, श्री जोर्ज येओ की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल की पहली मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें थाई राजकुमारी महा चकरी सीरिन्धोर्ण के साथ इंडोनेशिया के भूतपूर्व विदेश मंत्री, श्री हसन विराजुदा; और नालंदा विश्वविद्यालय के बोर्ड सदस्य और आईएपी सदस्य, प्रोफेसर लॉर्ड मेघनाद देसाई भी शामिल थे। इस वर्ष राजगीर आने वाले मुख्य अतिथियों में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री माधव कुमार नेपाल, सिंगापुर के वित्त मंत्री श्री के. शंमुघम, फ्रांसीसी राजदूत, श्री फ्रेंकोइस रिशेर, यूरोपियन युनियन डेलीगेशन, जिसमें, बेल्जियम, हंगरी, पुर्तगाल, स्लोवेनिया के राजदूत और डेलीगेशन प्रमुख शामिल थे। विश्वविद्यालय को ऑस्ट्रेलिया (दस लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर) और इंडोनेशिया (30,000 डॉलर) का अनुदान भी प्राप्त हुआ। बिहार सरकार की ओर से स्वतंत्र राजस्व के इस्तेमाल के लिए उपहार स्वरूप भूमि (110.99 एकड़) देने का वादा भी किया गया।

अकादमिक मोर्चे पर प्रमुख रहा नालंदा फैलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत, जिसके लिए विश्वविद्यालय को पांच फैलो मिलेः डॉ. एम. बी. रजनी, श्री अविराम शर्मा, डॉ. मिशेल बॉस, सुश्री एलेनोर मर्कुस्सें और डॉ. यिन केर जो क्रमशः भारत, नीदरलैंड, स्वीडन और सिंगापुर से थे। विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर प्रोग्राम के प्रारूप पर भी काम किया और फैकल्टी नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। पिछले साल शुरू हुई विशिष्ठ व्याख्यान श्रृंखला इस वर्ष भी जारी रही, जिसमें शामिल थेः प्रोफेसर थॉमस एडम लम्पकिन, मेक्सिको में मक्का और गेंहू सुधार के अंतर्राष्ट्रीय सेंटर के निदेशक जनरल; प्रोफेसर सैम वेनबर्ग, स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा और इतिहास के प्रोफेसर; प्रोफेसर प्रसेनजीत डोरा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में, एशिया रिसर्च इंस्टिट्यूट के निदेशक; और सर पीटर क्रेन, येल यूनिवर्सिटी में पर्यावरण विभाग के डीन। इस वर्ष नालंदा वार्तालाप श्रृंखला का आयोजन भी किया गया, जिसमें 10 से ज्यादा वार्तालाप आयोजित की गईं। इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज के सहयोग से राजगीर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया।

परिसर मोर्चे पर मुख्य काम वास्तुशिल्पीय डिजाइन प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा रहा। अहमदाबाद की वास्तुशिल्पीय कम्पनी, वास्तु शिल्प कन्सल्टेंट इस प्रतियोगिता में विजयी रही। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली में आठों प्रतियोगियों के मॉडल और डिजाइन की सार्वजानिक प्रदर्शनी आयोजित की गई। विश्वविद्यालय ने नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग (एनजेडईबी) पायलेट प्रोजेक्ट में भी भागीदारी की। इस परियोजना के तहत, यूएसएआईडी (पेस–डी) बीईई के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को परिसर में नेट जीरो एनर्जी (एनजेडई) स्तर हासिल करने में मदद करेगा।

आशा है कि यह रिपोर्ट आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आपको अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण की जरूरत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।

विषय–सूची

प्राक्कथन	**i**
अभिशासन	**2**
नए बोर्ड के संगठन तक नालंदा मेंटर ग्रुप ही शासकीय बोर्ड का कार्य संभालेगा	2
शासकीय बोर्ड के सदस्य	3
नालंदा विश्वविद्यालय शासकीय बोर्ड मीटिंग	7
अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल की पहली मीटिंग	9
मुख्य अतिथि से मुलाकात करते शासकीय बोर्ड के सदस्य	9
केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल 2013 का अनुमोदन	10
नालंदा विश्वविद्यालय के समर्थन में आठवें ईस्ट एशियन समिट में सात देशों ने अंतर–सरकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए	12
नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन पर भारत और चीन ने अंतर–सरकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए	13
जनवरी 2014 में कोरिया गणराज्य ने अंतर–सरकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए	14
विदेश मंत्रालय और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच हेडक्वार्टर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए	14
व्यय वित्त समिति ने नालंदा विश्वविद्यालय की परियोजना को अनुमोदित किया	15
नालंदा विश्वविद्यालय की वित्त समिति का गठन	17
नालंदा विश्वविद्यालय की भवन और निर्माण समिति का गठन	17
नालंदा विश्वविद्यालय के लिए निधि की पेशकश	18
नालंदा विश्वविद्यालय को थाईलैंड के योगदान की भारत ने प्रशंसा की	20
2013–14 में नालंदा विश्वविद्यालय के अधिकारियों की विशेष बैठक	20
2013–14 में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में मुख्य अतिथि	22
अकादमिक	**28**
बोर्ड में नालंदा फैलो	28
नालंदा विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर प्रोग्राम का अंतिम प्रारूप	29

फैकल्टी नियुक्ति प्रक्रिया में रिटायरमेंट की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई 29

फैकल्टी में पद के लिए विश्वविद्यालय में 500 निवेदन प्राप्त हुए 30

अकादमिक कैलेंडर 2014–15 का अंतिम रूप 30

नालंदा विश्वविद्यालय ने जनवरी में आईआईएएस के सहयोग से साझेदारी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन आयोजित किया 30

2013–14 विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला 32

नालंदा वार्तालाप श्रृंखला का विमोचन 34

नालंदा विश्वविद्यालय ने विश्व विरासत स्तरीय कार्यशाला का समर्थन किया 35

पेकिंग विश्वविद्यालय से नालंदा विश्वविद्यालय का गठबंधनः एक प्रस्ताव 36

परिसर **38**

वास्तु शिल्प विशेषज्ञों ने वास्तुशिल्प डिजाइन प्रतियोगिता जीती 38

एनजीएमए में आयोजित डिजाइन मॉडल की सार्वजानिक प्रदर्शनी 42

भारत में पहले नेट जीरो कैम्पस पर चर्चा के लिए प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन 43

विश्वविद्यालय ने लाइब्रेरी के डिजाइन के लिए वास्तु शिल्प विशेषज्ञों और सिंगापुर के वास्तुकार के साथ त्रिपक्षीय करार किया 44

राजगीर के अंतरिम परिसर का नवीनीकरण 44

नेट जीरो एनर्जी स्तर को हासिल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डवलपमेंट (यूएसएआईडी) पेस–डी नालंदा विश्वविद्यालय को तकनीकी सहयोग देगा 45

राजगीर में अस्थायी निवास किराये पर लेने की विश्वविद्यालय की योजना 46

मुख्य परिसर और अंतरिम परिसर में सुरक्षा सेवाओं को नियुक्त किया गया 46

वित्त **48**

Mr. SUDHIR KUMAR

अभिशासन

नए बोर्ड के संगठन तक नालंदा मेंटर ग्रुप ही शासकीय बोर्ड का कार्य संभालेगा

नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत, विश्वविद्यालय की शुरुआत में, नए बोर्ड के संगठन तक नालंदा मेंटर ग्रुप ही शासकीय बोर्ड का कार्य संभालेगा।

अधिनियम में दिए एक खंड के अनुसार शासकीय बोर्ड के पास निम्न शक्तियां हैं:

अधिनियम की धारा जो प्रबंधन मंडल की शक्तियों एवं कार्यों से संबंधित है, के अनुसार :

8. (1) विश्वविद्यालय और प्रबंधक के सभी निर्देशों और नीतियों के लिए संचालक बोर्ड उत्तरदायी रहेगा।

(2) शासकीय बोर्ड इन शक्तियों का इस्तेमाल निर्धारित संविधि के मद्देनजर कर सकता है:

नालंदा मेंटर ग्रुप अपनी शक्तियों के तहत शासकीय बोर्ड के कार्यों को साल भर के लिए या सदस्यों द्वारा उल्लिखित खंड (सी) से (जी) में दिए विभाग 7 के उप–विभाग (1), जो भी पहले हो, तक बर्खास्त कर सकता है।

इस खंड के तहत भारत सरकार नालंदा मेंटर ग्रुप से गुजारिश कर सकती है कि शासकीय बोर्ड के अपने कर्तव्यों की अदायगी करे, जब तक कि अधिनियम के अनुसार बोर्ड का गठन न हो जाए।

इस प्रकार शासकीय बोर्ड का कार्यकाल, जो 24 नवम्बर 2013 को समाप्त हो रहा था, उसे 22 नवम्बर 2013 को गजेट अधिसूचना जारी कर, नए बोर्ड के गठन तक आगे बढ़ाया गया।

शासकीय बोर्ड के सदस्य

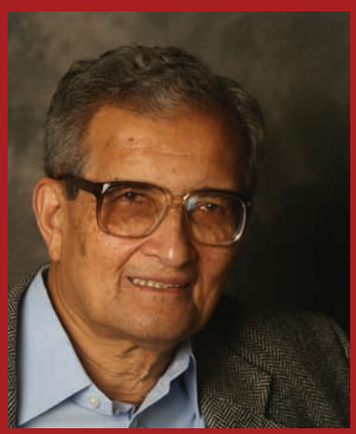

प्रोफेसर अमर्त्य सेन नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और विश्वविद्यालय के शासकीय बोर्ड के प्रमुख हैं। प्रोफेसर सेन लेमंट यूनीवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और हार्वर्ड यूनीवर्सिटी में भी अर्थशास्त्र और दर्शन के प्रोफेसर हैं। इससे पहले वह ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में कार्यरत थे। उनके शोध के विस्तृत दायरे में अर्थशास्त्र, दर्शन और निर्णय सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, अर्थशास्त्र कल्याण, जन स्वास्थ्य, लिंग अध्ययन, नैतिक और राजनीतिक दर्शन और शांति व युद्ध का अर्थशास्त्र शामिल है। आपको भारत रत्न और अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज से नवाजा जा चुका है।

श्री जॉर्ज येओ नालंदा विश्वविद्यालय के शासकीय बोर्ड के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल के प्रमुख हैं। आपको 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। आप वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, निकोलस बेग्र्मुएं इंस्टिट्यूट'स 21वीं सेंचुरी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड और आईइएसइ बिजनेस स्कूल के सदस्य भी हैं। इससे पूर्व, आप 23 सालों तक सिंगापुर सरकार के साथ सूचना और कला मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, व्यापार और उद्योग मंत्री और विदेश मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे।

श्री एन.के. सिंह बिहार से राज्य सभा सदस्य हैं। आप भारत सरकार में नौकरशाह रह चुके हैं, और भारत के व्यय और राजस्व सचिव का महत्वपूर्ण पद संभालते थे। आप प्रधानमंत्री के सचिव, राष्ट्रीय योजना आयोग के सदस्य और बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपने सुधार के राजनीति अर्थशास्त्र और राजनीतिक गठबंधनों की वास्तविकता पर कई किताबें और लेख लिखे हैं।

प्रोफेसर लॉर्ड मेघनाद देसाई सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ग्लोबल गवर्नंस से अवकाशप्राप्त प्रोफेसर हैं। आपने इसकी स्थापना 1992 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स (एलएसइ) में की थी। आप अप्रैल 1991 में, वेस्टमिंस्टर शहर के सेंट क्लेमेंट डेन में बैरन (इंग्लैंड में सबसे निचे दर्जे के लॉर्ड) भी बने। लॉर्ड देसाई 1990 में एलएसइ में डवलपमेंट स्टडीज इंस्टिट्यूट के संस्थापक सदस्य भी रहे। आप सालों से अर्थमितीय, समष्टि अर्थशास्त्र, मार्क्सवादी अर्थशास्त्र और विकास अर्थशास्त्र पढ़ाते रहे हैं।

प्रोफेसर प्रपोड अस्सवाविरुल्हाकर्ण चुलालोंग्कोर्ण यूनिवर्सिटी, बैंकाक में आर्ट्स फैकल्टी के अध्यक्ष हैं। आप चुलालोंग्कोर्ण यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इस्टर्न लैंग्वेज के प्रमुख भी रह चुके हैं। आपने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले से अपनी पीएचडी बौद्ध अध्ययन में की। आपने पाली–संस्कृत में स्नातक और स्नातकोत्तर चुलालोंग्कोर्ण यूनिवर्सिटी से की। आपके शोध का विषय शब्द व्युत्पत्ति, भाषा और समाज, पाली–संस्कृत साहित्य और धर्म–ग्रन्थ सम्बन्धी अध्ययन रहा है।

प्रोफेसर वांग गुन्ग्वु ईस्ट–एशियन इंस्टिट्यूट के अध्यक्ष और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में प्रोफेसर हैं। आप ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से अवकाशप्राप्त प्रोफेसर, एनयूएस में ली कुआं येव स्कूल ऑफ पब्लिक पोलिसी के अध्यक्ष, चाइनीज हैरिटेज सेंटर के उपाध्यक्ष और नानयांग टेकनोलोजीकल यूनिवर्सिटी में इंस्टिट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड डिफेन्स स्टडीज के बोर्ड मेम्बर हैं। प्रोफेसर वांग ब्रिटिश एम्पायर (सीबीइ) के कमांडर भी हैं। आप 1986 से 1995 तक होंग–कोंग यूनिवर्सिटी के उप–कुलाधिपति भी रह चुके हैं।

प्रोफेसर सुसुमु नाकानिशी नारा प्रीफेक्चर काम्प्लेक्स के निदेशक और जैपनीज स्टडीज के इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर में अवैतनिक प्रोफेसर हैं। आपके शोध का विषय जापानी संस्कृति में साहित्य और तुलनात्मक प्राचीन साहित्य है। आप शिन्तोइस्म, कोजिकी, निहोन शोकी और दूसरे जापानी साहित्य के सम्मानित विद्वान हैं। आपने प्राचीन जापानी लेखन पर अनेक किताबें लिखी हैं।

प्रोफेसर सुगाता बोस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास के गार्डिनर प्रोफेसर हैं। उपनिवेश और उपनिवेश पश्चात राजनीतिक अर्थशास्त्र, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में संबंध, यात्रा के अंतर–प्रांतीय कार्यक्षेत्र, समस्त भारत में व्यापार और संभावनाएं, भारतीय नैतिक उपदेश, राजनीतिक दर्शन और आर्थिक विचार आपकी स्कॉलरशिप के मुख्य विषय रहे हैं। आपने अंग्रेजी में अनुवाद कार्य किया है और टैगोर के गीतों की रिकॉर्डिंग को भी पब्लिश कराया है। आपको 1997 में गुग्गेन्हेइम फैलोशिप भी प्राप्त हुई।

प्रोफेसर वांग बंग्वेई पेकिंग यूनिवर्सिटी के इंस्टिट्यूट ऑफ ओरियंटल स्टडीज और ओरियंटल लिटरेचर रिसर्च सेंटर में निदेशक और प्रोफेसर हैं। आप पेकिंग यूनिवर्सिटी में इंडिया रिसर्च सेंटर के भी निदेशक हैं। आपकी शोध के विषय हैं: बौद्धिक साहित्य का अध्ययन, बौद्ध धर्म का इतिहास, चीन–भारत का सांस्कृतिक परस्पर प्रभाव खासकर बौद्ध सन्दर्भ में।

डॉ. तानसेन सेन न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी के बरूच कॉलेज में एशियन हिस्ट्री और रिलिजियन पढ़ाते हैं। आप नालंदा–श्रीविजया सेंटर, इंस्टिट्यूट ऑफ साउथईस्ट एशियन स्टडीज, सिंगापुर में भी पढ़ाने के लिए जाते हैं। आप एक विशेष लेख पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य 14वीं और 15वीं के मध्य एशिया में होने वाले संस्कृति के आदान–प्रदान पर नजर डालना है। इसके अतिरिक्त आप दक्षिण–अमेरिकी सिल्क रोड पर एक सहयोगपूर्ण प्रोजेक्ट, और भारत में चीनी समुदाय के इतिहास और अनुभवों पर एक वेबसाइट के निर्माण में भी व्यस्त हैं।

श्री अशोक के. कांथा ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में श्री संजय सिंह सचिव (पूर्व) के 30 अप्रैल 2013 को रिटायर होने के बाद, उनका पद संभाला। श्री कांथा श्रीलंका और मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त और एमईए के ईस्ट एशिया डिविजन में डायरेक्टर जनरल का पद भर संभाल चुके हैं। आप काठमांडू, नेपाल में भारतीय एम्बेसी में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन और होंग कोंग और मकउ में भारत के महावाणिज्य दूत रह चुके हैं। पटना यूनिवर्सिटी (1975) से इतिहास में स्नातक हो आपने 1977 में भारतीय विदेश सेवा में काम करना शुरू किया और 1979 से 1981 के बीच नानयांग यूनिवर्सिटी, सिंगापुर से चीनी भाषा का अध्ययन किया।

श्री अनिल वाधवा ने 6 जनवरी 2014 को, श्री अशोक के. कांथा के बीजिंग में भारत के राजदूत बनकर जाने के बाद, विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) का पद ग्रहण किया। इससे पूर्व श्री वाधवा थाईलैंड में भारत के राजदूत थे। आप पोलैंड में भारतीय राजदूत और ओमान में प्रोविजनल टेक्निकल सचिवालय में निदेशक/संयुक्त सचिव और बाद में हेग में भी तकनीकी सचिव की भूमिका निभा चुके हैं। धाराप्रवाह अंग्रेजी, हिंदी और चीनी भाषा बोलने वाले वाधवा चीनी इतिहास और मध्य कालीन भारत के इतिहास और आर्किटेक्चर में स्नातकोत्तर हैं। आपने 1979 में भारतीय विदेश सेवा में काम करना शुरू किया।

डॉ. गोपा सभरवाल नालंदा विश्वविद्यालय की उप–कुलाधिपति हैं। नालंदा आने से पूर्व आपने भारत के सर्वप्रथम लिबरल आर्ट्स कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज (महिला) में, 1993 में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलोजी की स्थापना की थी। अगले दो दशकों में इस डिपार्टमेंट का काम बेहद उल्लेखनीय रहा, इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सिंगापुर और जापान जैसे देशों के कई छात्र आए और यहां के कई छात्र इन देशों में गए। आपके शोध के विषयों में शहरी भारत में जातीय समूह, मानव शास्त्र और समाज इतिहास शामिल है। इन विषयों पर आपकी किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से जातीय समूह, कर्नाटक राज्य के बेलगाम में जातीयता पर शोध कर समाज शास्त्र में पीएचडी प्राप्त की।

नालंदा विश्वविद्यालय शासकीय बोर्ड मीटिंग

वर्ष 2013–14 के दौरान, शासकीय बोर्ड ने नई दिल्ली और पटना में मीटिंग की।

हमेशा की तरह शासकीय बोर्ड ने विश्वविद्यालय की स्थापना, विकास, विभिन्न प्रस्तावों पर स्वीकृति और विश्वविद्यालय के कार्यों जैसे मुद्दों पर चर्चा की।

2013–14 में शासकीय बोर्ड की मीटिंग

छठी मीटिंगः 20–21 जुलाई, 2013, नई दिल्ली

सातवीं मीटिंगः 23 फरवरी, 2014, पटना

सामने के पृष्ठ परः विश्वविद्यालय के शासकीय बोर्ड की सातवीं मीटिंग 23 फरवरी, 2014 को पटना में

विश्वविद्यालय के शासकीय बोर्ड की छठी मीटिंग 20–21 जुलाई, 2013 को नई दिल्ली में

मुख्य अतिथि से मुलाकात करते शासकीय बोर्ड के सदस्य

20 जुलाई 2013 को नालंदा विश्वविद्यालय के शासकीय बोर्ड के सदस्यों ने विश्वविद्यालय में मुख्य अतिथि बनकर आए भारत के राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। उन्होंने सदस्यों के साथ अपने विचार खुलकर साझा किए और विश्वविद्यालय की विभिन्न पहलुओं पर तरक्की की समीक्षा की।

उन्होंने विदेश मंत्री के तौर पर विश्वविद्यालय के साथ अपने पुराने संपर्क को याद किया। उन्होंने सदस्यों को इसकी परियोजना के लिए पूरे समर्थन का भी भरोसा दिलाया।

शासकीय बोर्ड के सदस्यों के साथ विश्वविद्यालय में मुख्य अतिथि बनकर आए भारत के राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी

अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल की पहली मीटिंग

विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल (आईएपी) की पहली मीटिंग का आयोजन 24 फरवरी, 2014 को राजगीर में किया गया। मीटिंग में नालंदा विश्वविद्यालय के बोर्ड के सदस्य और आईएपी के अध्यक्ष श्री जॉर्ज येओ; थाई राजकुमारी महा चकरी सीरिन्धोर्ण; इंडोनेशिया के भूतपूर्व विदेश मंत्री, श्री हसन विराजुदा; और नालंदा विश्वविद्यालय के बोर्ड सदस्य और आईएपी सदस्य, प्रोफेसर लॉर्ड मेघनाद देसाई भी शामिल थे।

थाई राजकुमारी महा चकरी सीरिन्धोर्ण राजगीर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल की पहली मीटिंग में भाषण देते हुए

कुलाधिपति और शासकीय बोर्ड के दूसरे सदस्य इस अवसर पर विशेष रूप से आमंत्रित थे।

इस अवसर पर बोलते हुए, थाई राजकुमारी महा चकरी सीरिन्धोर्ण ने कहा की उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में खासी दिलचस्पी है और थाईलैंड के निवासी इसमें हरसंभव मदद देने को तैयार हैं। उन्होंने बताया कि थाईलैंड के लोग नालंदा के विचार से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, और वे विश्वविद्यालय को मानवता की उम्मीद के रूप में देखते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय को वित्तीय मदद या दूसरे मामलों के लिए सरकार पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नालंदा पूरे एशिया में शिक्षा के स्तर में मानक सुधार करेगा। उन्होंने थाईलैंड आकर पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों को हरसंभव मदद की पेशकश की।

केन्द्रीय मंत्रीमंडल द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल 2013 का अनुमोदन

28 फरवरी 2014 को केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने सरकार द्वारा स्वीकृत और संसदीय कमिटी द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल, 2013 को अपना अनुमोदन दे दिया।

नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 में, विधेयक के प्रावधानों में कुछ को परिष्कृत करने का प्रयास करके विश्वविद्यालय के शासकीय ढांचे को सहज और शैक्षिक स्तर पर इसे विश्व स्तरीय बनाने की कोशिश की गई।

बिल 26 अगस्त 2013 को राज्य सभा में पेश किया गया था। सदन ने इसे बाहरी मामलों पर संसद की स्थायी समिति को प्रेषित कर दिया, जिसने अक्टूबर 4 और 22, 2013 की दो मीटिंग में इस पर चर्चा की। 17 दिसम्बर 2013 को बिल पर रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें सरकार द्वारा प्रस्तावित सुझावों को मान लिया गया।

स्थायी समिति ने निम्न मुख्य संशोधन पेश किए, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लियाः

1. विश्वविद्यालय के विषय में प्रस्तावना में "गैर–सरकारी, गैर–मुनाफा, स्व–शासकीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान अपने उद्देश्यों प्राप्ति में अकादमिक रूप से स्वतंत्र होंगे"।

2. नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के अंतर–सरकारी समझौता ज्ञापन, जो 10 अक्टूबर, 2013 को प्रभाव में आया, और अनुबंध कि जो देश इसकी स्थापना के उद्देश्य को स्वीकार करता है, वह इस समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता बन सकता है।

3. उप–कुलाधिपति शासकीय बोर्ड के सदस्य–सचिव की भूमिका भी निभाएगा।

4. नालंदा मेंटर ग्रुप शासकीय बोर्ड का दायित्व भी संभालेगा विभाग 7 के उप–विभाग (1) के खंड (सी) से (एच) के अनुसार।

5. हेडक्वार्टर एग्रीमेंट (एचक्यूए) में अकादमिक स्टाफ के विशेष अधिकारों और स्वाधीनता के बारे में विस्तार से बताया गया है, जो एग्रीमेंट की तारीख से लागू होते हैं।

6. ईस्ट एशिया समिट के भागीदार देशों के पांच सदस्यों के बजाय शासकीय बोर्ड में सात सदस्य होंगे, जो ईस्ट एशिया समिट के सात भागीदार और गैर–भागीदार देशों द्वारा नामांकित होंगे।

बेंदर सेरी बेगवान, ब्रूनेई में आंठवें ईस्ट एशिया समिट के अवसर पर अन्य पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह। 10 अक्टूबर, 2013 को सात देशों ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर अंतर–सरकारी एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

नालंदा विश्वविद्यालय के समर्थन में आठवें ईस्ट एशियन समिट में सात देशों ने अंतर–सरकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए भारत ने ईस्ट एशिया समिट के सात देशों के साथ एक करार पर हताक्षर किए।

10 अक्टूबर 2013 को, बेंदर सेरी बेगवान, ब्रुनेई में आंठवें ईस्ट एशिया समिट के अवसर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें शामिल देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कम्बोडिया, लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, म्यंमार, न्यूजीलैण्ड और सिंगापुर। ईस्ट एशिया समिट के दूसरे कई देशों ने संकेत किया कि वे भी आंतरिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे।

समझौता ज्ञापन की कुछ महत्वपूर्ण बातेंः

1. हस्ताक्षरकर्ता देश "नालंदा विश्वविद्यालय को ईस्ट एशिया समिट के भागीदार देशों में नेटवर्क और सहयोग बढ़ाने में मदद करेंगे। वे नालंदा विश्वविद्यालय के उपस्थित और प्रस्तावित केन्द्रों को छात्रों, शोधार्थियों और अकादमियों के लिए ज्ञान का बेहतर स्थल बनने में अपना सहयोग देंगे।"

2. नालंदा विश्वविद्यालय भागीदार देशों को ऐसे अकादमिक समुदाय बनाने में समर्थन देगा, जहां छात्र, शोधार्थी और विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय के बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र निर्मित कर पायें।

3. विश्वविद्यालय, उप–कुलाधिपति और अकादमिक स्टाफ, और जहां उपयुक्त हो उनके आश्रित और परिवार के सदस्य मेजबान देशों द्वारा उपलब्ध कराई सुविधाओं का इस्तेमाल कर पायेंगे।

4. मेजबान देश छात्रों, फेकल्टी और स्टाफ को विश्वविद्यालय में पढ़ाई और काम के लिए वीजा मुहैया कराएगा।

5. एमओयू के प्रभाव में आने के बाद, ईस्ट एशिया समिट का भागीदार कोई सा भी देश, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं, वह इस एमओयू की सारी सुविधाओं का अधिकारी होगा।

नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन पर भारत और चीन ने अंतर–सरकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

चीनी जनवादी गणराज्य भारत के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन पर अंतर–सरकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने वाला आठवां देश बना। भारत की विदेश सचिव, श्रीमती सुजाता सिंह और चीनी जनवादी गणराज्य के राजदूत श्री वी वी ने 23 अक्टूबर, 2013 को बीजिंग में इस पर हस्ताक्षर किए। यह भारत के प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह के चीन के दौरे के दौरान हुआ। ईस्ट एशिया समिट के सात देश पहले ही, 10 अक्टूबर, 2013 को ब्रुनेई में इस पर हस्ताक्षर कर चुके थे।

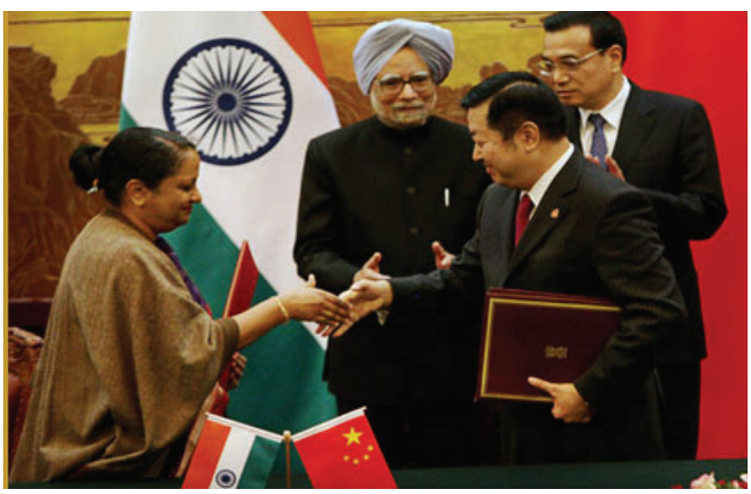

भारत की विदेश सचिव, श्रीमती सुजाता सिंह और चीनी जनवादी गणराज्य के राजदूत श्री वी वी ने अंतर–सरकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और चीनी प्रधानमंत्री ली किआंग मौजूद थे

जनवरी 2014 में कोरिया गणराज्य ने अंतर–सरकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

16 जनवरी 2014 को कोरिया गणराज्य ने कोरियाई राष्ट्रपति, सुश्री पार्क ग्युन हे के भारत दौरे के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और कोरिया गणराज्य नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की पहचान दिलाने के उद्देश्य से साथ आए। वे इसके माध्यम से एशियाई प्रतिभाओं को साथ में लाकर पुराने संबंध की नई खोज करना चाहते हैं। कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत श्री विष्णु प्रकाश और भारत में कोरिया के राजदूत डॉ. ली जून–ग्यु ने इस पर हस्ताक्षर किए।

विदेश मंत्रालय और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच हेडक्वार्टर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए

केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने 27 जून, 2013 को विदेश मंत्रालय और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच हेडक्वार्टर एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी। इस पर 20 जुलाई 2013 को भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव श्री राजन मथाई और कुलाधिपति प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने हस्ताक्षर किए। यह एग्रीमेंट विश्वविद्यालय और अकादमिक स्टाफ के सदस्यों को आवश्यक सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके माध्यम से विश्व से प्रतिभाओं को खींचकर विश्वविद्यालय के प्रांगण में लाया जा सके। एग्रीमेंट 22 जनवरी, 2014 को जारी किए जाने की तिथि से प्रभावशाली हो गया। इसे 20 फरवरी 2014 को राज्य सभा के सम्मुख पेश किया गया।

हेडक्वार्टर एग्रीमेंट (एचक्यूए) पर हस्ताक्षर होने के साथ विश्वविद्यालय के पहले सत्र के लिए दुनिया के सर्वोत्कृष्ट अध्यापकों को लाने की व्यवस्था की गई। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती नियम व शर्तों को लागू किए बिना नहीं हो सकती, जिसके लिए हेडक्वार्टर एग्रीमेंट का निष्कर्ष जरूरी है।

समझौते में वर्णित कुछ मुख्य तथ्य हैंः

1. विश्वविद्यालय के कार्य या परिसर को किसी तरह नुकसान पहुंचने की स्थिति में मेजबान देश उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठा सकता है।
2. किसी भी तरह के प्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क, ऑफिस सामग्री के आयत–निर्यात पर किसी भी तरह की बाधा से विश्वविद्यालय, उसकी संपत्ति, आय या दूसरी जायदाद अछूता रहेगा।
3. उप–कुलाधिपति और अकादमिक स्टाफ, जो मेजबान देश से ना होने पर भी, की आय, मानदेय, भत्ता और दूसरी परिलब्धियों को भी कर से मुक्त रखा जायेगा। उन्हें उपयुक्त वीजा का अधिकार; मेजबान देश में सेवा कार्यकाल के दौरान संपत्ति लाने ले जाने की छूट।
4. उप–कुलाधिपति और अकादमिक स्टाफ, जो मेजबान देश का हो, उनकी आय, मानदेय, भत्ता और दूसरी परिलब्धियों को भी कर से मुक्त रखा जायेगा।

व्यय वित्त समिति ने नालंदा विश्वविद्यालय की परियोजना को अनुमोदित किया

नालंदा विश्वविद्यालय को भी, भारत सरकार (जीओआई) की दूसरी परियोजनाओं की तरह ही व्यय वित्त समिति (ईएफसी) से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

इसी उद्देश्य से व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की एक मीटिंग वित्त सचिव की अध्यक्षता में 9 जुलाई 2013 को आयोजित की गई। उप–कुलाधिपति, डॉ. गोपा सभरवाल ने विश्वविद्यालय की प्रस्तावित लागत, पुनरावृति और पूंजी पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया।

मंत्रणा और समीक्षा के बाद, जो अंतिम राशि ईएफसी के अनुमोदन के लिए पेश की गई, वह 2727.10 करोड़ रुपये थी। बाद में, 20 जनवरी, 2014 को कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनोमिक्स अफेयर्स (सीसीईए) द्वारा संशोधित अनुमान पारित कर दिया गया।

नालंदा विश्वविद्यालय और विदेश मंत्रालय के बीच नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर अमर्त्य सेन और विदेश सचिव श्री रंजन मथाई ने हेडक्वार्टर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए।

नालंदा विश्वविद्यालय की वित्त समिति का गठन

10 अक्टूबर 2013 को विश्वविद्यालय की वित्त समिति का गठन किया गया। कमिटी में उप–कुलाधिपति और छह सदस्य शामिल हैं।

वित्त कमिटी के सदस्यः

1. डॉ. गोपा सभरवाल, उप–कुलाधिपति, नालंदा विश्वविद्यालय– **अध्यक्ष**
2. डॉ. पद्माकर मिश्रा, वित्त अधिकारी, नालंदा विश्वविद्यालय– **सदस्य–सचिव**
3. श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, संयुक्त सचिव (वित्त सलाहकार), मानव संसाधन मंत्रालय– **सदस्य**
4. श्रीमती दीपाली खन्ना, मेम्बर सेक्रेट्री, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स– **सदस्य**
5. श्रीमती जानकी कठपालिया, कोषपाल, दिल्ली विश्वविद्यालय– **सदस्य**
6. डॉ. अंजना शर्मा, अकादमिक योजना अध्यक्ष– **सदस्य**

रिपोर्ट के अनुसार एक साल में तीन मीटिंग आयोजित की गईः

पहली मीटिंगः 14 नवम्बर, 2013

दूसरी मीटिंगः 24 दिसम्बर, 2013

तीसरी मीटिंगः 20 फरवरी, 2014

नालंदा विश्वविद्यालय की भवन और निर्माण समिति का गठन

16 जनवरी, 2014 को विश्वविद्यालय के वित्त नियमन के बाद, भवन और निर्माण समिति का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता उप–कुलाधिपति और इसके आठ सदस्यों ने की, जिनमें से दो सदस्य विदेश मंत्रालय से भी थे। कमिटी की पहली मीटिंग का आयोजन 27 जनवरी, 2014 को किया गया।

भवन संरचना और कार्यकारी समिति के सदस्यः

1. डॉ. गोपा सभरवाल, उप–कुलाधिपति– **अध्यक्ष**
2. श्री ए. आर. रमानाथन, व्यावसायिक सलाहकार, आर्किटेक्चर और डिजाइन, नई दिल्ली– **सदस्य**
3. श्री ए. के. सिन्हा, सीपीडब्लूडी के भूतपूर्व अपर निदेशक जनरल, नई दिल्ली– **सदस्य**
4. श्री सुधीर कुमार, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, आईआईटी पटना प्रोजेक्ट जोन, सीपीडब्लूडी पटना– **सदस्य**
5. श्री बिनोय कुमार, विदेश मंत्रालय में अपर सचिव (वित्त सलाहकार) या उनके प्रतिनिधि– **सदस्य**
6. डॉ. अनुपम राय, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (नालंदा) या उनके प्रतिनिधि– **सदस्य**
7. डॉ. अंजना शर्मा, डीन अकादमिक योजना, नालंदा विश्वविद्यालय– **सदस्य**
8. डॉ. पद्माकर मिश्र, वित्त अधिकारी, नालंदा विश्वविद्यालय– **सदस्य–सचिव**

नालंदा विश्वविद्यालय के लिए निधि की पेशकश

ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण अध्ययन और चेयर ऑफ इकोलोजी की स्थापना के लिए 10 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की पेशकश की

नालंदा विश्वविद्यालय और ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करके तीन साल के प्रोजेक्ट को समर्थन दिया, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया पर्यावरण अध्ययन और चेयर ऑफ इकोलोजी की स्थापना के लिए 10 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की मदद देगा। स्टेटमेंट पर 18 नवम्बर 2013 को विदेश मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री सुश्री जूली बिशप की मौजूदगी में नालंदा विश्वविद्यालय की उप–कुलाधिपति डॉ. गोपा

सभरवाल और भारत में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत श्री पैट्रिक सक्लिंग ने हस्ताक्षर किए।

दोनों पक्षों ने माना कि पर्यावरण अध्ययन और चेयर ऑफ इकोलोजी की स्थापना से विश्वविद्यालय निरंतरता के आदर्शों के साथ आने वाली पीढ़ियों को विश्वविद्यालय के पुनरोद्धार के फायदे पहुंचा पायेगा। दोनों पक्षों ने माना कि 1 मार्च 2014 तक व्यवस्था को विकसित कर 30 जून 2014 तक फंड पहुंचना भी शुरू हो जायेगा।

इण्डोनेशिया ने विश्वविद्यालय को 30,000 डॉलर भेंट स्वरूप प्रदान किए

नालंदा विश्वविद्यालय को इण्डोनेशिया सरकार ने 30,000 डॉलर का योगदान दिया। वास्तव में यह नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के जकार्ता में दिए लेक्चर का वेतन था, जो उनकी गुजारिश पर इण्डोनेशिया सरकार ने विश्वविद्यालय को उपहार स्वरूप भेंट किया।

बिहार सरकार ने विश्वविद्यालय को स्वतंत्र आमदनी के स्रोत स्वरूप 110.99 एकड़ जमीन भेंट की

बिहार सरकार अगस्त 2013 में नालंदा विश्वविद्यालय को 110.99 एकड़ जमीन दान देने की घोषणा की। यह जमीन अभी अधिग्रहण में है और जल्द ही इसे विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दिया जायेगा।

विदेश मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री सुश्री जूली बिशप की मौजूदगी में नालंदा विश्वविद्यालय की उप–कुलाधिपति डॉ. गोपा सभरवाल और भारत में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत श्री पैट्रिक सक्लिंग ने स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए।

बिहार सरकार ने विश्वविद्यालय को स्वतंत्र आमदनी के स्रोत स्वरूप यह जमीन देने का निर्णय किया। इस अतिरिक्त जमीन का इस्तेमाल विश्वविद्यालय अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के तहत कर पायेगा।

नालंदा विश्वविद्यालय को थाईलैंड के योगदान की भारत ने प्रशंसा की

थाईलैंड की प्रधानमंत्री, सुश्री यिंगलक शिनावात्रा के निमंत्रण पर, भारत के प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह ने 30–31 मई, 2013 को थाईलैंड का औपचारिक दौरा किया था। इस अवसर पर, साझा वक्तव्य देते हुए दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने कहा कि दोनों देशों के बीच संस्थागत संबंध चरम पर हैं। वे विश्वविद्यालय–से–विश्वविद्यालय के प्रत्यक्ष सहयोग का स्वागत करते हुए, नालंदा विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं।

भारत ने नालंदा विश्वविद्यालय को थाईलैंड सरकार की ओर से दिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना अनुदान के लिए 100,000 यूएस डॉलर, साथ ही साथ थाईलैंड के निजी क्षेत्र द्वारा दिए 33,000 यूएस डॉलर के योगदान की प्रशंसा की। निजी योगदान छात्रों और अकादमी को बौद्धिक अध्ययन, दर्शन और तुलनात्मक धर्म के अध्ययन के लिए इस्तेमाल किया जायेगा।

2013–14 में नालंदा विश्वविद्यालय के अधिकारियों की विशेष बैठक

नालंदा विश्वविद्यालय टीम ने आगंतुक से मुलाकात की

उप–कुलाधिपति डॉ. गोपा सभरवाल और डीन अकादमिक योजना, डॉ. अंजना शर्मा 29 मई, 2013 को आगंतुक से मिले। सचिव (आर्थिक संबंध), पिनाक चक्रवर्ती और विदेश मंत्रालय (एमईए) के संयुक्त सचिव, डॉ. जितेन्द्र नाथ मिश्रा (नालंदा) भी वहां उपस्थित थे।

उप–कुलाधिपति ने आगंतुक को विभिन्न स्तरों पर चल रहे विकास कार्यों के विषय में बताया और आगंतुक ने एमईए से लंबित मसलों के परिणाम और नालंदा विश्वविद्यालय के विशेष स्तर पर रचनात्मकता के बारे में जानकारी ली।

उप–कुलाधिपति ने ईसीएएफ के एजीएम में शिरकत की

उप–कुलाधिपति, डॉ. गोपा सभरवाल जून में एशियन पीस स्टडी के लिए यूरोपीय संघ की वार्षिक मीटिंग में भाग लेने के लिए, जून में फ्रांस गई थीं। वहां उन्होंने 3 जून 2013 को जीआईपी ईसीएएफ विधान अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। नालंदा विश्वविद्यालय संयुक्त रिसर्च प्रोग्राम और दूसरे पाठ्यक्रमों के लिए ईसीएएफ के साथ मिलकर काम करेगा। ईसीएएफ के साथ मिलकर काम करने वाला नालंदा विश्वविद्यालय पहला भारतीय संस्थान है।

एलएसई में अकादमिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अधिकारी से उप–कुलाधिपति की मुलाकात

उप–कुलाधिपति, डॉ. गोपा सभरवाल जून, 2013 में यू.के. भी गई थीं। वहां उन्होंने कुलाधिपति प्रोफेसर अमर्त्य सेन और बोर्ड मेम्बर प्रोफेसर लोर्ड मेघनाद देसाई से मुलाकात के अलावा लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स में लाइब्रेरी प्रबंधन पर विशेष जोर देते हुए, परिसर की स्थापना के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण मुलाकातें भी कीं।

उप–कुलाधिपति और डीन (एपी) ने आईसीएएस द्वारा आयोजित 4–दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया

उप–कुलाधिपति, डॉ. गोपा सभरवाल और डीन अकादमिक योजना, डॉ. अंजना शर्मा आईसीएएस के सम्मेलन में

उप–कुलाधिपति, डॉ. गोपा सभरवाल और डीन अकादमिक योजना, डॉ. अंजना शर्मा ने मकउ में 23 से 27 जून, 2013 को इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एशिया स्कोलर्स (आईसीएएस) द्वारा आयोजित 4–दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया। जहां उप–कुलाधिपति ने शासकीय बोर्ड मेम्बर, डॉ. तानसेन सेन द्वारा आयोजित "एशियन स्टडीज इन एशिया" सत्र में भाग लिया। चर्चा में भाग लेने वाले दूसरे वक्ता थे प्रसेनजित डोरा (नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर), प्रोफेसर मारिस दिओक्नो (यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपिंस), डॉ. साइमन शेन (चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ होंग कोंग) और सरमन मुखर्जी (प्रेजिडेंसी यूनिवर्सिटी)।

उप–कुलाधिपति और डीन (एपी) येल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इलनॉइज, अर्बाना शम्पेन, (यूएसए) में

उप–कुलाधिपति, डॉ. गोपा सभरवाल और डीन अकादमिक योजना, डॉ. अंजना शर्मा को सितम्बर 2013 में, येल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इलनॉइज, अर्बाना शम्पेन, (यूएसए) में साझेदारी के सिलसिले में आमंत्रित किया गया। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति से भी मुलाकात की, जहां उन्होंने प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर चर्चा की। नालंदा विश्वविद्यालय के बोर्ड मेम्बर, प्रोफेसर सुगाता बोस ने भी एक मीटिंग में भाग लिया।

उप–कुलाधिपति ने लंदन में सम्मेलन में भाग लिया

उप–कुलाधिपति, डॉ. गोपा सभरवाल ने ब्रिटिश काउंसिल के निमंत्रण पर, फरवरी 2014 में लंदन में एक सम्मेलन में भाग लिया, जिसका विषय था "उच्च शिक्षा में नया दृष्टिकोणः भारत से साझेदारी"।

2013–14 में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में मुख्य अतिथि

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम का राजगीर दौरा

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बिहार के मुख्यमंत्री, श्री नितीश कुमार के साथ, 11 मई, 2013 को राजगीर का दौरा किया। वहां उन्होंने शासकीय बोर्ड के कुछ सदस्यों के साथ परियोजनाओं के विकास पर चर्चा की। उन्होंने विश्वास दिलाया कि विश्वविद्यालय को कभी फंड की कमी से नहीं गुजरना पड़ेगा।

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम का बिहार के मुख्यमंत्री, श्री नितीश कुमार के साथ, 11 मई, 2013 को राजगीर का दौरा

नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नेपाल में भारत के राजदूत के साथ नालंदा विश्वविद्यालय दौरा

नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री माधव कुमार नेपाल ने 27 जुलाई, 2013 को राजगीर में, नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया। उप–कुलाधिपति ने उन्हें विश्वविद्यालय के विकास के बारे में बताया। दौरे के दौरान उन्होंने नए परिसर के मॉडल के मास्टर प्लान और वास्तु डिजाइन में खास दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने कहा कि नए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत से देशों का सहयोग मिला है, जिससे इसने भरोसा जताया है कि यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्थान साबित होगा। उन्होंने भारत और नेपाल के पुराने ऐतिहासिक संपर्क, और दोनों देशों में पर्यटक केन्द्र के रूप में बौद्ध स्थल बनाये जाने की योजना की भी चर्चा की। नेपाल में भारत के राजदूत, श्री जयंत प्रसाद भी इस दौरे पर श्री माधव कुमार के साथ आए थे।

उप–कुलाधिपति, डॉ. गोपा सभरवाल नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री माधव कुमार नेपाल, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के मॉडल के मास्टर प्लान के बारे में बताते हुए

सिंगापुर के विदेश मंत्री का नालंदा विश्वविद्यालय दौरा

सिंगापुर के विदेश और कानून मंत्री, श्री के. शंमुगम ने 29 जुलाई, 2013 को नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया। वह 13 सदस्यीय दल के साथ आए थे, जिसमें उस कमिटी के सदस्य भी थे, जिसका गठन नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के लिए फंड एकत्र करने के लिए किया गया था। श्री शंमुगम ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर और विश्वविद्यालय के नए परिसर स्थल का भी दौरा किया। उन्होंने

उप–कुलाधिपति, डॉ. गोपा सभरवाल सिंगापुर के विदेश मंत्री, श्री के. शंमुगम और उनकी पत्नी डॉ. सीता शंमुगम को, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के मॉडल के मास्टर प्लान के बारे में बताते हुए

नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण स्थल पर सिंगापुर से आया दल

खुशी व्यक्त की कि सिंगापुर के कई निवासी नालंदा परियोजना से, इसे ईस्ट एशिया से जोड़ने के लिए जुड़े थे। उन्होंने इस ऐतिहासिक स्थल को देखकर खुशी व्यक्त की और बताया कि यहां आने का मकसद यह देखना था कि सिंगापुर कैसे इसके विकास में अपना योगदान दे सकता है। श्री शंमुगम नालंदा के आंतरिक परिसर में भी गए, जहां उन्होंने मास्टर प्लान का मॉडल देखा और डिजाइन की प्रशंसा की।

यूरोपीय संघ प्रतिनिधि मंडल का नालंदा विश्वविद्यालय दौरा

यूरोपीय संघ के चार देशोंः बेल्जियम, हंगरी, पुर्तगाल, स्लोवेनिया के राजदूत और यूरोपीय संघ प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख ने 28 अक्टूबर 2013 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया। उप–कुलाधिपति ने उन्हें विश्वविद्यालय के विकास और अंतर–सरकारी समझौता ज्ञापन के बारे में बताया, जिसका उद्देश्य नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में स्थापित करना है, और जिस पर ईस्ट एशिया समिट के आठ देश पहले ही हस्ताक्षर कर चुके थे। राजदूतों ने संकेत किया कि इनके देश भी नालंदा विश्वविद्यालय की परियोजनाओं में अपना सहयोग देने का प्रयास करेंगे। उप–कुलाधिपति ने भी आशा व्यक्त की कि राजदूतों के दौरे से विश्वविद्यालय को उनके देशों के साथ करीबी संबंध बनाने में मदद मिलेगी।

उप–कुलाधिपति, डॉ. गोपा सभरवाल, यूरोपीय संघ के राजदूतों को नालंदा विश्वविद्यालय का मास्टर प्लान दिखाते हुए

उप–कुलाधिपति, डॉ. गोपा सभरवाल, यूरोपीय संघ के राजदूतों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण स्थल पर

यूरोपीय संघ के 28 देशों के राजदूतों की नालंदा के सिलसिले में सचिव (ईस्ट) से मुलाकात

यूरोपीय संघ के चार देशों के राजदूतों के दौरे के बाद सचिव (ईस्ट) ने यूरोपीय संघ के 28 देशों के राजदूतों को आमंत्रित कर उन्हें नालंदा विश्विवद्यालय के बारे में बताकर 29 जनवरी को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया। उप–कुलाधिपति, डॉ. गोपा सभरवाल और डीन अकादमिक योजना, डॉ. अंजना शर्मा ने विश्वविद्यालय की ओर से प्रेजेंटेशन पेश की।

फ्रांसीसी राजदूत का नालंदा विश्वविद्यालय दौरा

फ्रांसीसी राजदूत, श्री फ्रेंकोइस रिशेर ने 3 दिसम्बर, 2013 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया। उप–कुलाधिपति, डॉ. गोपा सभरवाल ने उनका स्वागत कर उन्हें नालंदा के बारे में प्रेजेंटेशन पेश की।

उप–कुलाधिपति, डॉ. गोपा सभरवाल, फ्रांसीसी राजदूत, श्री फ्रेंकोइस रिशेर को विश्वविद्यालय की योजना के बारे में बताते हुए

यूनिवर्सिटी ऑफ इलनॉइज, अर्बाना शम्पेन, (यूएसए) के प्रोफेसर

उप–कुलाधिपति, डॉ. गोपा सभरवाल, फ्रांसीसी राजदूत, श्री फ्रेंकोइस रिशेर को विश्वविद्यालय की योजना के बारे में बताते हुए

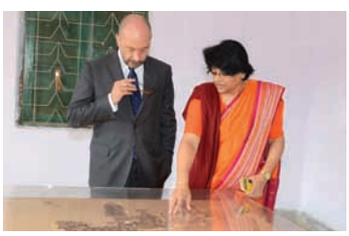

स्टीवन सोनका और फिलीपिंस के इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट (आईआरआरआई) के बिजनेस मॉडल के विशेषज्ञ श्री अल्फ्रेड शिमिडली ने 5 दिसम्बर, 2013 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया। आईआरआरआई के पास बड़ी संख्या में ऐसे दाता हैं, जो अनुदान मुहैया करते हैं, जिनमें यूएस–एड; बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउन्डेशन और कई यूनिवर्सिटी पार्टनर भी शामिल हैं। बिहार अभी उनके शोध का मुख्य केंद्र है, इसलिए वह नालंदा में काम को समझने आए थे। वे नालंदा विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इकोलोजी और एन्वायरमेंट स्टडीज के साथ काम कर रहे हैं।

यूनिवर्सिटी ऑफ इलनॉइज (अर्बाना शम्पेन) और आईआरआरआई के विशेषज्ञ नालंदा के एक गांव में

BAT AM

अकादमिक

बोर्ड में नालंदा फैलो

जनवरी 2013 में नालंदा फैलोशिप प्रोग्राम का आयोजन किया गया और विश्वविद्यालय को स्कूल ऑफ इकोलोजी और एन्वायरमेंट स्टडीज के लिए 34 आवेदन और स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज के लिए 53 आवेदन प्राप्त हुए।

चयन समिति ने आखिरकार सात शोधार्थियों को नालंदा फैलोशिप 2013–14 के लिए चुनाः

स्कूल ऑफ इकोलोजी और एन्वायरमेंट

1. सुश्री एलेओनोर मर्कुस्सें – स्वीडन से
2. श्री अविराम शर्मा – भारत से

स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज

1. डॉ. मुरारी झा – भारत से
2. डॉ. बिल मैक – जापान से
3. डॉ. यिन केर – सिंगापुर से
4. डॉ. मिशेल बॉस – नीदरलैंड से
5. डॉ. एम बी रजनी – भारत से

हालांकि, डॉ. मुरारी झा और डॉ. बिल मैक ने क्रमशः लेडेन और टोक्यो में अपनी वर्तमान अकादमिक व्यस्तताओं के चलते वर्ष 2013–14 में विश्वविद्यालय में दाखिला न ले पाने पर अफसोस जाहिर किया।

नालंदा फैलो 2013–14

डॉ. एम बी रजनी 15 जून 2013 को एक फैलो के रूप में जुड़ी। उनकी शोध का विषय थाः *नालंदा में जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल।*

श्री अविराम शर्मा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी के छात्र, जो 16 जून 2013 को जूनियर फैलो के रूप में जुड़े। उनकी शोध का विषय थाः *दक्षिण बिहार के बदलती कृषि को समझनाः सिंचाई तकनीक, पानी का अधिकार और जीवनयापन की चुनौतियां।*

डॉ. मिशेल बॉस ने 8 जुलाई, 2013 को फैलो के रूप में जुड़े। उनकी शोध का विषय था: *बिहार में नए व्यवसाय: परिवर्तनीयता का अध्ययन, मर्दानगी और मध्य वर्ग।*

सुश्री एलेओनोर मर्कुर्स्सें साउथ एशिया इंस्टिट्यूट (एसएआई), हेडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग की पीएचडी छात्रा ने 1 अगस्त, 2013 को विश्वविद्यालय में जूनियर फैलो के रूप में दाखिला लिया। उनके शोध का विषय था: *सहायता के नियम: 1934 बिहार भूकंप के बाद राहत और निर्माण कार्यों की राजनीति।*

डॉ. यिन केर, (सोरबोन, चंपतपेपैरिस) ने 28 फरवरी, 2014 को विश्वविद्यालय के इतिहास अध्ययन विभाग में फैलो के रूप में दाखिला लिया। उनके शोध का विषय था: निराकार सत्य को देखना और दिखाना: *म्यांमार के बगई औंग सो (1924–1990) आधुनिक बौद्ध पेंटिंग्स। राजगीर की रहने वाली वह पहली नालंदा फैलो बनीं।*

नालंदा विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर प्रोग्राम का अंतिम प्रारूप

जुलाई 2013 में, शासकीय बोर्ड की छठी मीटिंग के दौरान विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर प्रोग्राम की संरचना, अवधि और दाखिले की प्रक्रिया का अंतिम प्रारूप निर्धारित हो गया।

बोर्ड ने फिर से दोहराया कि नालंदा विश्वविद्यालय की डिग्री प्रारंभ से ही दक्षता का संकेत देगी, इसके लिए स्नातक स्तर के छात्रों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जायेगा।

विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर प्रोग्राम दो साल का होगा। हालांकि विशेष प्रशिक्षित छात्र इसे एक साल में ही पूरा कर पाएंगे। दूसरे विश्वविद्यालय से क्रेडिट्स हस्तांतरित किए जा सकते हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया कठोर ही होगी।

दाखिले के सिलसिले में बोर्ड का कहना है कि अंग्रेजी की दक्षता को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए।

फैकल्टी नियुक्ति प्रक्रिया में रिटायरमेंट की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई

शासकीय बोर्ड ने फैकल्टी की विशेषताओं को परिभाषित किया कि किस तरह का स्टाफ विश्वविद्यालय को नियुक्त करना चाहिए और नालंदा

विश्वविद्यालय के स्टाफ की रिटायरमेंट आयु 65 साल होनी चाहिए, जिसमें आवश्यकतानुसार 3 साल और फिर 2 साल बढ़ाने की संभावना हो।

फैकल्टी में पद के लिए विश्वविद्यालय में 500 निवेदन प्राप्त हुए

नालंदा विश्वविद्यालय को संस्थापक फैकल्टी के पद के लिए 500 निवेदन प्राप्त हुए, जो इसके दो नए स्कूलः स्कूल ऑफ इकोलोजी एंड एन्वायरमेंट स्टडीज और स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज के लिए थे। आवेदकों में अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों का अनुपात ज्यादा था।

आवेदन दिसम्बर 2013 से 25 जनवरी, 2014 के बीच जमा करवाए जा सकते थे।

आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आधार पर संभाली गई। सभी आवेदकों ने अपने आवेदन वेब–मेल आईडी पर जमा करवाए थे, और इन आवेदनों पर बाद में विश्वविद्यालय ने चर्चा की।

आवेदकों का चयन दोनों स्कूलों के लिए गठित चयन समिति द्वारा किया गया। साल समाप्ति पर, आवेदकों के साक्षात्कार लिए जाने लगे। दोनों स्कूलों के लिए 10–10 शिक्षक नियुक्त किए जाने थे।

अकादमिक कैलेंडर 2014–15 का अंतिम रूप

विश्वविद्यालय में 16–16 सप्ताह के दो सत्र निर्धारित किए गए। पतझड़ सत्र का आरम्भ 27 अगस्त 2014 से होगा, और बसंत सत्र का आरम्भ 6 जनवरी 2015 से। इनके बाद एक दो सप्ताह का छोटा सत्र भी आयोजित किया जायेगा, 4 मई 2015 से 15 मई 2015 के बीच।

नालंदा विश्वविद्यालय ने जनवरी में आईआईएएस के सहयोग से साझेदारी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन आयोजित किया

नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने 6 से 8 जनवरी 2014 को, राजगीर में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मलेन का शीर्षक था "सांस्कृतिक धरोहरः पर्यावरण, पारिस्थितिकी और इतिहास"। इसका आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय और

इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर एशियन स्टडीज (आईआईएएस) ने संयुक्त रूप से किया। आईआईएएस लीडेन, नीदरलैंड का शोध और विनिमय संस्थान है। यह एशिया के बहु विषयक और तुलनात्मक अध्ययन को प्रोत्साहित करता है, और इसके लिए (अंतर)राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करता है।

सम्मलेन में मुख्य वक्ता थेः

1. एन्सेंग हो, सांस्कृतिक मानव–शास्त्र के प्रोफेसर, ड्यूक यूनिवर्सिटी।
2. फ्रेडरिक आशेर, कला इतिहास प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, हिस्ट्री ऑफ आर्ट नेशनल कमिटी के अध्यक्ष और अर्काइव्स ऑफ एशियन आर्ट के दक्षिण एशियाई संपादक।
3. अकिरा मात्सुई, सेंटर ऑफ आर्केओलोजिकल ऑपरेशन की निदेशक, और क्योटो विश्वविद्यालय में ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज की प्रोफेसर।

आईआईएएस की साझेदारी से आईआईएएस राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन

इन तीन मुख्य वक्ताओं के अलावा सम्मेलन के नौ सत्रों में 20 अंतर्राष्ट्रीय और 7 राष्ट्रीय वक्ताओं ने भाग लिया।

2013–14 विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला

प्रोफेसर थॉमस एडम लम्पकिन का व्याख्यानः प्रोफेसर थॉमस एडम लम्पकिन मेक्सिको में मक्का और गेहूं के इंटरनेशनल इम्प्रोव्मेंट सेंटर के निदेशक और बोर्लौग इंस्टिट्यूट ऑफ साउथ एशिया (भारत) के निदेशक जनरल हैं। उन्होंने 19 अगस्त 2013 को दिल्ली और 20 अगस्त 2013 को पटना में **"बदलती जलवायु, जनसंख्या और आहारः क्या भारतीय और चीनी कृषि अस्तित्व में रह पाएगी?"** विषय पर व्याख्यान दिया।

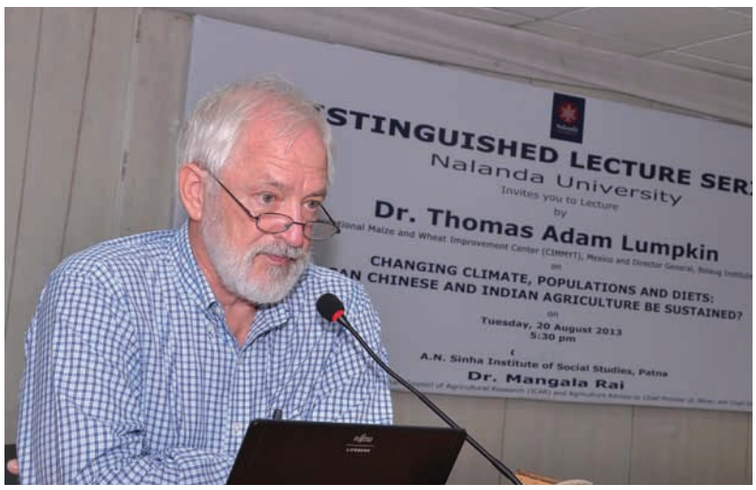

थॉमस एडम लम्पकिन "बदलती जलवायु, जनसंख्या और आहारः क्या भारतीय और चीनी कृषि अस्तित्व में रह पाएगी?" विषय पर व्याख्यान देते हुए

प्रोफेसर सैम विनबर्ग का व्याख्यानः स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा और इतिहास के प्रोफेसर सैम विनबर्ग ने 29 अक्टूबर, 2013 को दिल्ली में **"क्या इतिहास की कोई उपयोगिता है ?"** पर व्याख्यान दिया।

प्रोफेसर प्रसेनजीत डोरा का व्याख्यानः सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी में एशिया रिसर्च इंस्टिट्यूट के डायरेक्टर और मानविकी के प्रोफेसर प्रसेनजीत डोरा ने 25 नवम्बर 2013 को पटना में और 28 नवम्बर 2013 को दिल्ली में **"उत्कृष्टता की निरंतरता और संकटः एशिया का नजरिया"** विषय पर व्याख्यान दिया।

प्रोफेसर सैम विनबर्ग "क्या इतिहास की कोई उपयोगिता है?" विषय पर व्याख्यान देते हुए"

प्रोफेसर प्रसेनजीत डोरा "उत्कृष्टता की निरंतरता और संकटः एशिया का नजरिया" विषय पर व्याख्यान देते हुए

सर पीटर क्रेन का व्याख्यानः येल यूनिवर्सिटी में पर्यावरण विभाग के जूनियर डीन और बॉटनी के प्रोफेसर सर पीटर क्रेन 20 मार्च 2014 को दिल्ली में और 21 मार्च 2014 को पटना में **"गिन्क्गोः समय के साथ भुला दिया गया पेड़"** विषय पर व्याख्यान दिया।

सर पीटर क्रेन "गिन्क्गोः समय के साथ भुला दिया गया पेड़" विषय पर व्याख्यान देते हुए

नालंदा वार्तालाप श्रृंखला का विमोचन

जुलाई 2013 में नालंदा विश्वविद्यालय ने नालंदा फैलो, डॉ. एम.बी. रजनी के व्याख्यान **"जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के इस्लेमाल से नालंदा का अध्ययन"** से वार्तालाप श्रृंखला का विमोचन किया।

वर्ष के दौरान आयोजित दूसरे वार्तालाप इस प्रकार हैं:

"राष्ट्रवाद और बड़े बांधः आधुनिक भारत को बाढ़ नियंत्रित बनाना" जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर स्टडीज इन साइंस पोलिसी के सहायक प्रोफेसर रोहन डिसूजा, 8 अगस्त 2013, दिल्ली।

"दक्षिण बिहार में कृषि रूपांतरण को समझनाः सिंचाई तकनीक, पानी अधिकार और जीवनयापन की चुनौतियां" श्री अविराम शर्मा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी के छात्र, 14 अगस्त 2013, दिल्ली।

"नदी क्षेत्रफल और राज्यः औपनिवेशिक भारत में संपत्ति और जगह बदलती नदियां" योर्क (यूके) विश्वविद्यालय में आधुनिक इतिहास के प्रवक्ता, नितिन सिन्हा, 4 सितम्बर, 2013, दिल्ली।

"खबरों और तकनीक का नेटवर्कः पत्रकारिता के इतिहास और 19वीं सदी के दक्षिण और पूर्व एशिया की मूल वस्तु की ओर" ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी (यूके), पोस्टडोक्टोरल रिसर्च, अमिला बों, 26 सितम्बर 2013, दिल्ली।

"सहायता के नियमः 1934 बिहार भूकंप के बाद राहत और निर्माण कार्यों की राजनीति" सुश्री एलेओनोर मर्कुस्सें साउथ एशिया इंस्टिट्यूट (एसएआई), हेडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग की पीएचडी छात्रा, 3 अक्टूबर, 2013, दिल्ली।

"जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के इस्लेमाल से नालंदा का अगला अध्ययन" नालंदा फैलो, डॉ. एम.बी. रजनी, 10 अक्टूबर 2013, दिल्ली।

"ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रः प्रवास, पार देशियवाद और जातिवाद का सवाल" डॉ. मिशेल बॉस, फैलो नालंदा विश्वविद्यालय, 24 अक्टूबर 2013, दिल्ली।

"जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के इस्लेमाल से नालंदा के विस्तार का अगला अध्ययन" नालंदा फैलो, डॉ. एम.बी. रजनी, 10 अक्टूबर 2013, दिल्ली।

"मध्य वर्ग के नए व्यवसायः मांसपेशी, मर्दानगी और परिवर्तनीयता" डॉ. मिशेल बॉस नालंदा फैलो, 27 मार्च, दिल्ली।

नालंदा विश्वविद्यालय ने विश्व विरासत स्तरीय कार्यशाला का समर्थन किया

नालंदा विश्वविद्यालय ने 11 और 12 नवम्बर 2013 को राजगीर में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से "नालंदा महाविहार के खोदकर निकाले गए अवशेष" नाम से एक कार्यशाला का आयोजन किया। यह वर्कशॉप प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की फाइल में नामांकित कराकर, विश्व धरोहर स्थल बनाने का भाग है।

पेकिंग विश्वविद्यालय से नालंदा विश्वविद्यालय का गठबंधनः एक प्रस्ताव

विश्वविद्यालय को पेकिंग विश्वविद्यालय से गठबंधन करने का प्रस्ताव मिला, जिससे दोनों संस्थानों के बीच अकादमिक गठबंधन स्थापित हो सके। इस प्रस्ताव में विकास कार्यक्रम का विनियम और अध्ययन व वैज्ञानिक शोध में सहयोग शामिल है।

एक प्रस्ताव नालंदा विश्वविद्यालय में इंडिया–चीन स्टडीज (जिसमें संयुक्त डिग्री प्रोग्राम भी शामिल होगा) के लिए ह्वेन त्सांग सेंटर की स्थापना करने का भी है।

"नालंदा महाविहार के खोदकर निकाले गए अवशेष" नामक कार्यशाला के सहभागी, जिसका आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय ने 11 और 12 नवम्बर 2013 को राजगीर में किया

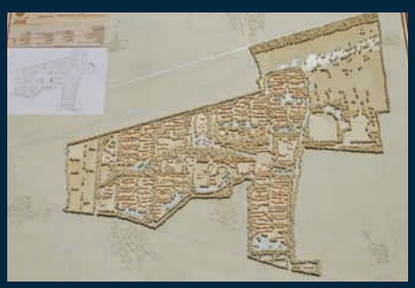

परिसर

वास्तु शिल्प विशेषज्ञों ने वास्तुशिल्प डिजाइन प्रतियोगिता जीती

6 मई 2013 को, अहमदाबाद की वास्तुशिल्प कंपनी के वास्तु शिल्प विशेषज्ञ राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वास्तुशिल्प डिजाइन प्रतियोगिता में विजेता रहे। वास्तु शिल्प विशेषज्ञों में प्रमुख थे डॉ. बी.वी. दोशी और श्री राजीव काठपलिया।

17 जनवरी, 2013 को चयन प्रक्रिया के तहत आठ वास्तुकारों और वास्तुशिल्प कंपनियों को डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुना गया। इसके बाद कंपनियों को एक–एक प्रतियोगिता फाइल सौंप दी गई, जिसमें प्रतियोगिता के नियम, निर्देश, डिजाइन निर्देश, वास्तुशिल्पीय प्रोग्राम और दूसरी जानकारियां दी गई थीं।

चयनित कंपनियों को परिसर के लिए अपने डिजाइन और मॉडल, जिसमें निर्माण के पहले दौर का विवरण हो, को 25 अप्रैल 2013 तक विश्वविद्यालय के पास जमा करवाना था।

प्रतियोगिता का संचालन वास्तुशिल्प परिषद (सीओए) के मानकों के अनुसार और विजेता का चयन भी सीओए के दिशा–निर्देशों के अनुसार किया गया।

सामने के पृष्ठ पर

ऊपर की पंक्ति और मध्यः विजेता वास्तु शिल्प कन्सल्टेंट का मॉडल
निचली पंक्तिः दूसरी प्रविष्टियों के मॉडल

प्रतियोगिता के लिए गठित वास्तुशिल्प डिजाइन समिति में निम्न सदस्य थेः

1. डॉ. लिउ थाई केर, सिंगापुर के भूतपूर्व नगरीय योजनाकार प्रमुख
2. प्रोफेसर ओसामु इशियामा, वासेदा यूनिवर्सिटी, जापान
3. प्रोफेसर ली शियोदोंग, शिन्गुआ यूनिवर्सिटी, बीजिंग
4. प्रोफेसर नीलकंठ छाया, सीईपीटी यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद
5. श्री एन.के. सिंह, संसद सदस्य, नालंदा विश्वविद्यालय शासकीय बोर्ड सदस्य
6. प्रोफेसर लॉर्ड मेघनाद देसाई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, नालंदा विश्वविद्यालय शासकीय बोर्ड सदस्य
7. डॉ. गोपा सभरवाल, उप–कुलाधिपति, नालंदा विश्वविद्यालय

वास्तुशिल्प डिजाइन समिति

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित दो–सदस्यीय (श्री प्रसाद वैद्य और श्री संजय प्रकाश) तकनीकी कमिटी का गठन भागीदारों के नेट–जीरो प्रोजेक्शन का मूल्यांकन करने के लिए किया गया। कमिटी ने 29 और 30 अप्रैल, 2013 को जमा किए हुए नेट–जीरो परिप्रेक्ष्य की जांच और डिजाइन समिति को रिपोर्ट सौंपने के लिए मुलाकात की।

वास्तुशिल्पीय डिजाइन समिति के सदस्यों ने भी 3 और 4 मई, 2013 को राजगीर में निर्माण स्थल का जायजा लिया, जिससे वे जमा किए हुए मॉडल को परिसर के परिप्रेक्ष्य में सही तरह से जांच सकें।

वास्तुशिल्पीय डिजाइन समिति ने 5 और 6 मई, 2013 को जमा किए हुए मॉडल का मूल्यांकन किया। प्रतियोगिता के दौरान गुप्तता का नियम लागू किया। प्रतियोगियों को व्यक्तिगत पहचान का 4–अंकों का नंबर चुन कर उसे लिफाफे को सील कर लगाने को कहा गया, जो अंतिम निर्णय आने तक गुप्त रहने वाला था।

वास्तुशिल्पीय डिजाइन समिति मॉडल का मूल्यांकन करते हुए

गहन विचार–विमर्श के बाद समिति ने दो प्रविष्टियों का चयन किया: वास्तु शिल्प कन्सल्टेंट और वीरेंद्र खन्ना एंड एसोसिएट्स और आईडीओएम इन्जेनेरिया वाय कंसलटोरिया, एस.ए. जेवी को क्रमशः पहला और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ।

समिति ने दोनों प्रस्तावों की समग्रता से जांच की और इनके वैचारिक योजना, स्पष्टता और नालंदा के नजरिए को प्रस्तुत करने की क्षमता से विजेता को घोषित किया। समिति ने वास्तु शिल्प कन्सल्टेंट को प्रतियोगिता का विजेता यह कहते हुए घोषित किया कि उनका मॉडल विश्वविद्यालय की प्राचीन धरोहर, उद्देश्य और महत्वकांक्षा को बेहतर तरीके से प्रतिपादित करता है।

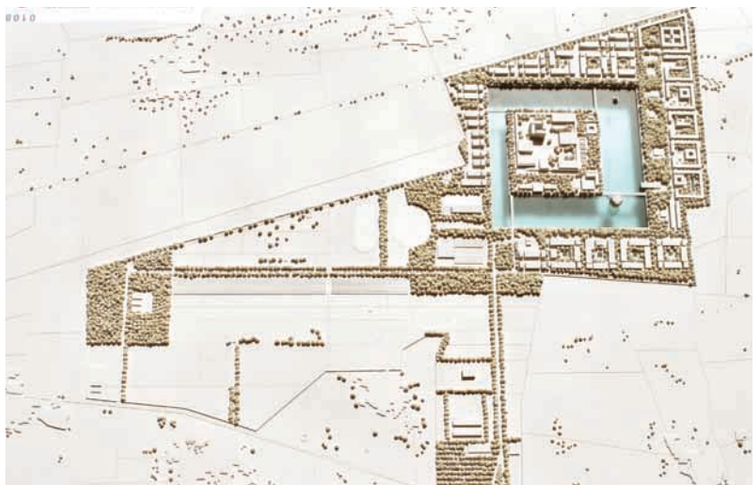

ऊपरः प्रथम स्थान विजेता, वास्तु शिल्प कन्सल्टेंट का मॉडल

नीचेः द्वितीय स्थान विजेता, वीरेंद्र खन्ना एंड एसोसिएट्स और आईडीओएम इन्जेनेरिया वाय कंसलटोरिया का मॉडल

एनजीएमए में आयोजित डिजाइन मॉडल की सार्वजनिक प्रदर्शनी

प्रतियोगिता के बाद, विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया की सभी मॉडल और डिजाइन को जनता के समक्ष रखने के लिए सार्वजनिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रदर्शनी को व्यवसायिक वास्तुकार और छात्रों के साथ–साथ सामान्य जन द्वारा भी काफी सराहा गया। इसका आयोजन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (एनजीएमए), नई दिल्ली में किया गया। पहले इसका आयोजन 8 से 18 मई तक किया जाना था, लेकिन लोकप्रियता के चलते इसे पहले 31 मई और फिर बाद में 7 जून, 2013 तक बढ़ाया गया।

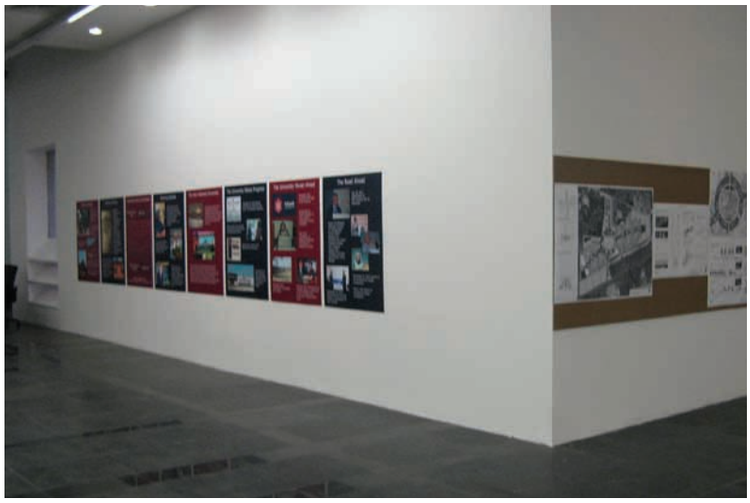

नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (एनजीएमए), नई दिल्ली में आठ मॉडल और ड्राइंग की सार्वजनिक प्रदर्शनी

भारत में पहले नेट जीरो कैम्पस पर चर्चा के लिए प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन

विश्वविद्यालय के आग्रह पर, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित, डॉ. बी.वी. दोशी और वास्तु शिल्प कन्सल्टेंट के प्रमुख श्री राजीव काठपलिया और वास्तु शिल्प प्रतियोगिता डिजाइन के विजेता ने नई दिल्ली में, 16 मई, 2013 को प्रेस से मुलाकात कर डिजाइन से जुड़े उनके सवालों का जवाब दिया।

वास्तु शिल्प कन्सल्टेंट के प्रमुख और विजेता कंपनी, शासकीय बोर्ड के सदस्यों से मुलाकात करते हुए

पद्मश्री सम्मान से सम्मानित, डॉ. बी. वी. दोशी और वास्तु शिल्प कन्सल्टेंट के प्रमुख श्री राजीव काठपलिया, वास्तु शिल्प प्रतियोगिता डिजाइन के विजेता और उप–कुलाधिपति डॉ. गोपा सभरवाल दिल्ली में प्रेस से मुखातिब होते हुए

विश्वविद्यालय ने लाइब्रेरी के डिजाइन के लिए वास्तु शिल्प विशेषज्ञों और सिंगापुर के वास्तुकार के साथ त्रिपक्षीय करार किया

सिंगापुर ने विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के लिए डिजाइन और उसका निर्माण कराने की पेशकश की। उन्होंने श्री लिउ थाई केर को लाइब्रेरी का मुख्य शिल्पकार नियुक्त किया।

विश्वविद्यालय की सिंगापुर के साथ सहमति है कि उनके द्वारा बनाया गया लाइब्रेरी का डिजाइन जहां विश्वविद्यालय की जरूरतों को पूरा करेगा, वहीं उसके मास्टर प्लान से तालमेल भी रखेगा।

विश्वविद्यालय वास्तुशिल्प विशेषज्ञ और लाइब्रेरी के डिजाइन को दिशा–निर्देश देने के लिए श्री श्री लिउ थाई केर के साथ त्रिपक्षीय करार करने की योजना बना रहा है।

राजगीर के अंतरिम परिसर का नवीनीकरण

विश्वविद्यालय ने 19 नवम्बर, 2012 को पटना के वास्तुशिल्पी कपूर एसोसिएट्स को राजगीर के 4–एकड़ के अंतरिम परिसर के पुनरुद्धार में सलाह और वास्तुशिल्पिय सेवाएं देने का काम सौंपा, जिससे वे राजगीर के परिसर में कार्यालय और कुछ रिहायशी इमारतों के निर्माण का काम करवा सकें। पुनरुद्धार की लागत लगभग 2.52 करोड़ रुपये आंकी गई थी। बिहार सरकार के सड़क निर्माण विभाग ने 21 अगस्त, 2013 को इसे तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया।

इसके पश्चात खुले टेंडर के माध्यम से काम सौंपने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं, लेकिन 4 निविदाओं में से कोई भी काम के लिए तकनीकी रूप से प्रशिक्षित नहीं पाया गया।

मामले की चर्चा बिहार सरकार और मुख्यमंत्री के साथ की गई, जहां तय किया गया कि विश्वविद्यालय बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बीआरपीएनएनएल) को काम सौंप देगा, जिन्होंने पहले भी विश्वविद्यालय परिसर की बाहरी दीवार का निर्माण किया था।

भवन और निर्माण समिति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय ने इस मसले को 24 दिसम्बर, 2013 को वित्त समिति की मीटिंग में पेश किया। समिति ने सहमति जताई कि पुनरुद्धार के काम को बीआरपीएनएनएल को सौंपना चाहिए।

तब तक, एमईए की सलाह पर, बीआरपीएनएनएल को प्रारंभिक दौर की तैयारियां शुरू करने को कहा गया, क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय की ओर से अभी तक काम का अनुमोदन नहीं आया था। इस दौरान वित्तीय अधिनियम भी प्रकाशित हुआ, और भवन और निर्माण समिति का औपचारिक गठन भी। 27 जनवरी 2014 को समिति ने इस मसले पर चर्चा की, हालांकि शहरी विकास मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई अनुमोदन नहीं मिला था।

समिति ने विश्वविद्यालय को सलाह दी कि वह सीधे बिहार सरकार से इजाजत मांगे कि काम उन्हीं की एजेंसी द्वारा किया जाना था। इसके अनुसार एक याचिका बिहार सरकार के मुख्य सचिव को भेजी गई। 7 फरवरी, 2014 को विश्वविद्यालय को एमईए की ओर से एक पत्र मिला कि वे बीआरपीएनएनएल को काम रोकने का आदेश दे दें, क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय ने अभी तक अनुमोदन नहीं दिया है। इन सारी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप वर्ष 2014 तक पुनरुद्धार कार्य शुरू नहीं हो पाया था।

नेट जीरो एनर्जी स्तर को हासिल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डवलपमेंट (यूएसएआईडी) पेस–डी नालंदा विश्वविद्यालय को तकनीकी सहयोग देगा

17 मई 2013, को विश्वविद्यालय ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी (बीईई), ऊर्जा मंत्रालय के साथ यूएसएआईडी साझेदारी के अंतर्गत एडवांस क्लीन एनर्जी–डेप्लोयमेंट (पेस–डी) प्रोग्राम के लिए नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग (एनजेडईबी) पायलट प्रोजेक्ट के लिए "भागीदारी पत्र" पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना के तहत, यूएसएआईडी (पेस–डी) बीईई के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को परिसर में नेट जीरो एनर्जी (एनजेडई) स्तर हासिल करने में मदद करेगा।

नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग एक ऐसी इमारत होगी, जहां पर ऊर्जा की खपत बिलकुल शून्य होगी, मतलब एक साल में इमारत में

जितनी ऊर्जा की खपत होगी, उतनी ही अक्षत ऊर्जा वहां उत्पन्न कर ली जाएगी। ये इमारतें वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को नहीं बढ़ाएंगी, इसीलिए इन्हें एनजेडईबी कहा जाता है।

नालंदा विश्वविद्यालय में एनजेडईबी के सफल कार्यान्वयन के बाद, भारत में एनजेडईबी के निर्माण और डिजाइन को बढ़ावा मिलेगा।

राजगीर में अस्थायी निवास किराये पर लेने की विश्वविद्यालय की योजना

चूंकि विश्वविद्यालय के परिसर का निर्माण कार्य नहीं हो पाया, तो विश्वविद्यालय को फैकल्टी, गैर–अकादमिक स्टाफ और छात्रों के लिए अस्थायी निवास की जरूरत है। तीनों श्रेणियों के लिए उचित निवास ढूंढ़ने के लिए नगर में कुछ होटल से चर्चा की जा रही है। इसके लिए इच्छुक पक्षों से निविदाएं मंगवाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है।

मुख्य परिसर और अंतरिम परिसर में सुरक्षा सेवाओं को नियुक्त किया गया

बाहरी दीवार का काम पूरा होने के बाद विश्वविद्यालय ने परिसर की सुरक्षा की दिशा में कदम उठाया। अनुभवी सुरक्षा एजेंसियों से निविदा मंगवाने के बाद, 16 जून 2013 को सिलीगुड़ी की एएमएस कम्पनी को आंतरिक परिसर की 24 घंटे सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस एजेंसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को 36 सुरक्षाकर्मी और 3 सुपरवाइजर मुहैया कराये।

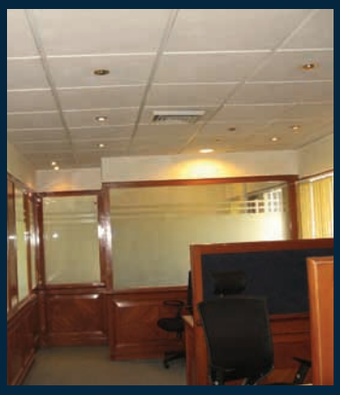

Dr. ANJANA SHARMA
Dr. GOPA SABHARWAL

वित्त

वित्तीय वर्ष 2012–13 का विश्वविद्यालय का सालाना बिना लेखा परीक्षा खाता जुलाई 2013 को नई दिल्ली में होने वाली शासकीय बोर्ड की मीटिंग में अनुमोदन के लिए पेश किया गया। इसके बाद भारत के ऑडिटर जनरल और लेखा–नियंता की ऑफिस टीम ने उसे ऑडिट किया। बाद में लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ सालाना रिपोर्ट को वित्त कमिटी और फिर फरवरी 2014 को होने वाली शासकीय बोर्ड की मीटिंग के समक्ष पेश किया गया।

2011–12 का वार्षिक खाता, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट को 18 दिसम्बर 2013 को लोक सभा और 13 फरवरी 2014 को राज्य सभा में पेश किया गया।

फरवरी 2014 को हुई मीटिंग में बोर्ड को सूचित किया गया कि 2013–14 में अपेक्षित फंड 14.63 करोड़ रूपये को कम किया जाए, जो आर्किटेक्ट कॉन्ट्रेक्ट के लिए था। अब कॉन्ट्रेक्ट के विलंबित होने की स्थिति में यूनीवर्सिटी इसका खर्च उठाने की अनुमति नहीं देगी। वित्तीय वर्ष 2014–15 का अनुमानित बजट 367.0 करोड़ था, जिसे शासकीय बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया।

शासन, अकादमिक, परिसर और वित्तीय स्तर पर विश्वविद्यालय के मसले निम्न अधिकारियों द्वारा संभाले जाते हैंः

1. उप कुलाधिपतिः डॉ. गोपा सभरवाल
   (gsabharwal@nalandauniv.com)
2. अकादमिक योजना, अध्यक्षः डॉ. अंजना शर्मा
   (asharma@nalandauniv.com)
3. वित्त अधिकारीः डॉ. पद्माकर मिश्रा
   (pmishra@nalandauniv.com)
4. सलाहकारः श्री सुधीर कुमार
   (skumar@nalandauniv.com)
   प्रशासन अधिकारीः श्री एस एल शर्मा
   (slsharma@nalandauniv.com)
5. व्यावसायिक सलाहकार, आर्किटेक्चर और डिजाइनः
   श्री ए. आर. रामनाथन
   (ar.ramanthan@gmail.com)

नई दिल्ली कार्यालय

द्वितीय तल, काउंसिल फॉर सोशल डेवेलोपमेंट
संघरचना, 53, लोदी स्टेट, नई दिल्ली - 110 003
दूरभाष संख्या : +91-11 24618352, +91-11 26172328
फैक्स संख्या : +91-11 24618351

राजगीर कार्यालय

राजगीर, जिला नालंदा, पिन - 803 115
बिहार, भारत
www.nalandauniv.edu.in